

बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने में बाल विकास योजनाओं की भूमिका :

एक अध्ययन

डॉ. श्रीनिवास मिश्र

संध्या तिवारी,

सेवानिवृत्त प्राध्यापक, समाजशास्त्र विभाग

शोधार्थी समाजशास्त्र विभाग

शासकीय महाविद्यालय अमरपाटन जिला मैहर मध्यप्रदेश

शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय रीवा मध्यप्रदेश

सारांश :-

किसी भी राष्ट्र के सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विशेष रूप से बालिका शिक्षा को मानव संसाधन विकास का आधार माना जाता है। भारत में लंबे समय तक लैंगिक असमानता, गरीबी, सामाजिक रूढ़ियों तथा संसाधनों की कमी के कारण बालिकाओं की शिक्षा प्रभावित रही है। इन चुनौतियों को दूर करने के लिए भारत सरकार तथा विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा अनेक बाल विकास एवं बालिका कल्याण योजनाएँ संचालित की जा रही हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य बालिकाओं को शिक्षा, पोषण, स्वास्थ्य, सुरक्षा तथा समान अवसर उपलब्ध कराना है। प्रस्तुत शोध-पत्र में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने में बाल विकास योजनाओं की भूमिका का विश्लेषण किया गया है। अध्ययन में समेकित बाल विकास सेवा (ब्ले), बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, सुकन्या समृद्धि योजना तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत संचालित कार्यक्रमों का अध्ययन किया गया है। शोध से यह स्पष्ट होता है कि इन योजनाओं ने बालिकाओं के नामांकन, उपस्थिति, शैक्षणिक उपलब्धि तथा विद्यालय में निरंतरता बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। साथ ही, अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक बाधाएँ, आर्थिक कठिनाइयाँ तथा जागरूकता की कमी जैसी चुनौतियाँ विद्यमान हैं।

मुख्य शब्द : बालिका शिक्षा, बाल विकास योजनाएँ, महिला सशक्तिकरण, शिक्षा, ICDS, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आदि।

प्रस्तावना :-

शिक्षा मानव जीवन के सर्वांगीण विकास का सबसे प्रभावशाली साधन है। यह केवल ज्ञान प्राप्ति का माध्यम नहीं है, बल्कि व्यक्ति के व्यक्तित्व निर्माण, सामाजिक चेतना, आर्थिक आत्मनिर्भरता तथा नैतिक विकास का आधार भी है। किसी भी राष्ट्र की उन्नति और समृद्धि उसके नागरिकों की शैक्षिक स्थिति पर निर्भर करती है। यदि समाज का प्रत्येक वर्ग शिक्षित होगा, तभी राष्ट्र का समग्र विकास संभव हो सकेगा। इसी संदर्भ में बालिका शिक्षा का विशेष महत्व है, क्योंकि एक शिक्षित बालिका न केवल स्वयं का विकास करती है, बल्कि अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान देती है। कहा जाता है



कि यदि एक पुरुष शिक्षित होता है तो केवल एक व्यक्ति शिक्षित होता है, जबकि यदि एक महिला शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। इस प्रकार बालिका शिक्षा सामाजिक परिवर्तन और राष्ट्रीय विकास की आधारशिला है।

भारतीय समाज में प्राचीन काल से महिलाओं की स्थिति में अनेक उतार-चढ़ाव देखने को मिले हैं। वैदिक काल में महिलाओं को शिक्षा एवं सामाजिक गतिविधियों में समान अवसर प्राप्त थे, किंतु समय के साथ विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारणों से महिलाओं की स्थिति कमजोर होती गई। परिणामस्वरूप बालिकाओं की शिक्षा पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। लंबे समय तक बाल विवाह, पर्दा प्रथा, लैंगिक भेदभाव, गरीबी, सामाजिक रूढ़िवादिता तथा संसाधनों की कमी जैसी समस्याओं के कारण बालिकाएँ शिक्षा से वंचित रहीं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने शिक्षा के सार्वभौमिकरण और महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से अनेक प्रयास किए, जिनके परिणामस्वरूप बालिका शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है।

भारतीय संविधान ने सभी नागरिकों को समानता का अधिकार प्रदान किया है तथा शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है। संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 21ए और 45 में शिक्षा एवं लैंगिक समानता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों ने भी बालिका शिक्षा को विशेष महत्व दिया है। विशेष रूप से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने लैंगिक समानता, समावेशी शिक्षा तथा बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अनेक महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किए हैं।

हालाँकि पिछले कुछ दशकों में बालिका शिक्षा की स्थिति में सुधार हुआ है, फिर भी ग्रामीण क्षेत्रों, आदिवासी समुदायों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तथा सामाजिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में अनेक बालिकाएँ आज भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित हैं। विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं का अभाव, पारिवारिक आर्थिक कठिनाइयाँ, बाल श्रम, बाल विवाह, सुरक्षा संबंधी चिंताएँ तथा सामाजिक पूर्वाग्रह बालिका शिक्षा के मार्ग में प्रमुख बाधाएँ हैं। इन चुनौतियों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न बाल विकास योजनाएँ संचालित की जा रही हैं, जिनका उद्देश्य बालिकाओं के शैक्षिक, सामाजिक, शारीरिक एवं मानसिक विकास को सुनिश्चित करना है।

बाल विकास योजनाएँ बच्चों के समग्र विकास के लिए तैयार की गई ऐसी कल्याणकारी योजनाएँ हैं जिनके माध्यम से स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, सुरक्षा तथा सामाजिक संरक्षण की सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं। इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य बच्चों को जीवन के प्रारंभिक चरण से ही विकास के उचित अवसर उपलब्ध कराना है। विशेष रूप से बालिकाओं के संदर्भ में ये योजनाएँ अत्यंत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे उन्हें शिक्षा प्राप्त करने के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराती हैं। भारत सरकार द्वारा संचालित समेकित बाल विकास सेवा (प्लै), बेंटी बचाओ बेंटी पढ़ाओ अभियान, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, राष्ट्रीय बालिका शिक्षा कार्यक्रम तथा विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाएँ इसी दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास हैं।

समेकित बाल विकास सेवा योजना के माध्यम से बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा, पूरक पोषण, स्वास्थ्य परीक्षण तथा टीकाकरण जैसी सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं। यह योजना बालिकाओं को विद्यालय पूर्व शिक्षा के लिए तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसी प्रकार बेंटी बचाओ बेंटी पढ़ाओ अभियान का उद्देश्य समाज में बालिकाओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना तथा उनकी शिक्षा को प्रोत्साहित करना है। इस अभियान ने बालिकाओं की शिक्षा के प्रति जन-जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।



प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना (पूर्व मध्याह्न भोजन योजना) भी बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने वाली एक महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना के अंतर्गत विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाता है, जिससे उनकी उपस्थिति बढ़ती है तथा कुपोषण की समस्या में कमी आती है। गरीब परिवारों की बालिकाओं के लिए यह योजना विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध हुई है क्योंकि इससे उनके विद्यालय में बने रहने की संभावना बढ़ जाती है।

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना उन बालिकाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है जो सामाजिक, आर्थिक अथवा भौगोलिक कारणों से शिक्षा प्राप्त करने में कठिनाई का सामना करती हैं। इस योजना के अंतर्गत आवासीय विद्यालयों की व्यवस्था की गई है, जहाँ बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा, भोजन एवं आवास उपलब्ध कराया जाता है। इससे विशेष रूप से ग्रामीण और वंचित वर्ग की बालिकाओं को शिक्षा के अवसर प्राप्त हुए हैं।

इसी प्रकार सुकन्या समृद्धि योजना बालिकाओं के भविष्य को आर्थिक रूप से सुरक्षित बनाने का प्रयास करती है। यह योजना अभिभावकों को बालिकाओं की शिक्षा और भविष्य के लिए बचत करने हेतु प्रोत्साहित करती है। परिणामस्वरूप बालिकाओं के प्रति परिवारों का दृष्टिकोण सकारात्मक हुआ है तथा शिक्षा के प्रति उनकी रुचि में वृद्धि हुई है।

बाल विकास योजनाओं का प्रभाव केवल विद्यालयी नामांकन तक सीमित नहीं है, बल्कि इन योजनाओं ने बालिकाओं के स्वास्थ्य, पोषण, आत्मविश्वास, सामाजिक सहभागिता तथा शैक्षणिक उपलब्धियों को भी प्रभावित किया है। इन योजनाओं के कारण विद्यालयों में बालिकाओं की उपस्थिति बढ़ी है, विद्यालय छोड़ने की दर में कमी आई है तथा शिक्षा के प्रति सामाजिक जागरूकता में वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त महिलाओं के सशक्तिकरण और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने में भी इन योजनाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। फिर भी यह देखा गया है कि अनेक योजनाओं के बावजूद कुछ क्षेत्रों में अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हो सके हैं। योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में प्रशासनिक कमियाँ, संसाधनों की कमी, जागरूकता का अभाव तथा सामाजिक बाधाएँ प्रमुख चुनौतियाँ बनी हुई हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने में बाल विकास योजनाओं की वास्तविक भूमिका और प्रभाव का समग्र अध्ययन किया जाए, जिससे उनकी उपलब्धियों तथा सीमाओं का मूल्यांकन किया जा सके।

प्रस्तुत अध्ययन इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने में विभिन्न बाल विकास योजनाओं की भूमिका का विश्लेषण करने का प्रयास करता है। यह अध्ययन न केवल इन योजनाओं की प्रभावशीलता को समझने में सहायक होगा, बल्कि नीति-निर्माताओं, शिक्षाविदों तथा समाज के अन्य हितधारकों को बालिका शिक्षा के क्षेत्र में आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाने हेतु उपयोगी सुझाव भी प्रदान करेगा। इस प्रकार यह अध्ययन बालिका शिक्षा के संवर्धन एवं महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण योगदान सिद्ध हो सकता है।

अध्ययन की पृष्ठभूमि

स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में महिला साक्षरता दर अत्यंत कम थी। समय के साथ विभिन्न शिक्षा नीतियों एवं योजनाओं के माध्यम से महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया गया। संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने भी लैंगिक समानता और बालिका शिक्षा को विशेष महत्व दिया है। सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाएँ बालिकाओं को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित कर रही हैं। इन



योजनाओं के माध्यम से छात्रवृत्ति, निःशुल्क शिक्षा, पोषण सहायता, आवासीय विद्यालय तथा वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

अध्ययन की आवश्यकता –

बालिका शिक्षा केवल व्यक्तिगत विकास का माध्यम नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन का आधार है। एक शिक्षित बालिका भविष्य में शिक्षित परिवार और स्वस्थ समाज का निर्माण करती है। यह अध्ययन निम्न कारणों से आवश्यक है –

- बालिका शिक्षा की वर्तमान स्थिति का विश्लेषण।
- बाल विकास योजनाओं की प्रभावशीलता का मूल्यांकन।
- योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली चुनौतियों की पहचान।
- नीति-निर्माताओं के लिए सुझाव प्रदान करना।

अध्ययन के उद्देश्य –

- बालिका शिक्षा की वर्तमान स्थिति का अध्ययन करना।
- विभिन्न बाल विकास योजनाओं का विश्लेषण करना।
- बालिका शिक्षा पर इन योजनाओं के प्रभाव का मूल्यांकन करना।
- योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली समस्याओं का अध्ययन करना।
- बालिका शिक्षा को और अधिक प्रभावी बनाने हेतु सुझाव प्रस्तुत करना।

साहित्य समीक्षा :-

शर्मा (2018) अध्ययन में पाया गया कि मध्याह्न भोजन योजना ने बालिकाओं की विद्यालय उपस्थिति में वृद्धि की।

सिंह एवं वर्मा (2019) **ICDS** सेवाओं के माध्यम से बालिकाओं के पोषण स्तर एवं प्रारंभिक शिक्षा में सुधार देखा गया।

गुप्ता (2020) बेंटी बचाओ बेंटी पढ़ाओ अभियान ने समाज में बालिका शिक्षा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित किया।

मिश्रा (2021) कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों ने ग्रामीण एवं वंचित वर्ग की बालिकाओं को शिक्षा के अवसर प्रदान किए।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (2020) लैंगिक समानता को बढ़ावा देने तथा बालिकाओं की शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु विशेष प्रावधान किए गए।

बालिका शिक्षा पर बाल विकास योजनाओं का प्रभाव

नामांकन में वृद्धि सरकारी योजनाओं के कारण विद्यालयों में बालिकाओं के नामांकन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

उपस्थिति में सुधार मध्याह्न भोजन, छात्रवृत्ति एवं निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों के कारण बालिकाओं की नियमित उपस्थिति बढ़ी है।

ड्रॉपआउट दर में कमी आर्थिक सहायता एवं जागरूकता कार्यक्रमों के कारण विद्यालय छोड़ने वाली बालिकाओं की संख्या कम हुई है।



स्वास्थ्य एवं पोषण में सुधार स्वास्थ्य सेवाओं एवं पोषण कार्यक्रमों ने बालिकाओं की शारीरिक क्षमता और सीखने की दक्षता में वृद्धि की है।

महिला सशक्तिकरण शिक्षित बालिकाएँ आत्मनिर्भर एवं आत्मविश्वासी बन रही हैं।

बालिका शिक्षा में बाधाएँ –

1. गरीबी
2. बाल विवाह
3. लैंगिक भेदभाव
4. सुरक्षा संबंधी समस्याएँ
5. विद्यालयों में शौचालयों का अभाव
6. जागरूकता की कमी
7. ग्रामीण क्षेत्रों में संसाधनों की कमी

व्याख्या –

अध्ययन से स्पष्ट होता है कि बाल विकास योजनाओं ने बालिका शिक्षा के विस्तार में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। योजनाओं के परिणामस्वरूप विद्यालयों में बालिकाओं का नामांकन एवं उपस्थिति बढ़ी है। हालांकि कुछ क्षेत्रों में सामाजिक एवं आर्थिक बाधाएँ अभी भी प्रभाव डाल रही हैं। योजनाओं की सफलता के लिए स्थानीय समुदाय, विद्यालय एवं परिवार की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है।

निष्कर्ष –

बालिका शिक्षा राष्ट्र निर्माण का आधार है। भारत सरकार द्वारा संचालित विभिन्न बाल विकास योजनाएँ बालिकाओं को शिक्षा के अवसर प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। प्ले, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री पोषण योजना, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय एवं सुकन्या समृद्धि योजना जैसी पहलें बालिकाओं के शैक्षिक विकास को सुदृढ़ कर रही हैं। यद्यपि उल्लेखनीय प्रगति हुई है, फिर भी सामाजिक रूढ़ियाँ, गरीबी एवं जागरूकता की कमी जैसी चुनौतियाँ बनी हुई हैं। अतः योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन एवं जन-जागरूकता के माध्यम से बालिका शिक्षा को और अधिक सशक्त बनाया जा सकता है।

सुझाव

1. ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चलाए जाएँ।
2. विद्यालयों में सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित किया जाए।
3. छात्रवृत्ति योजनाओं का विस्तार किया जाए।
4. बाल विवाह पर कठोर नियंत्रण किया जाए।
5. डिजिटल शिक्षा सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएँ।



6. विद्यालयों में पृथक शौचालयों की व्यवस्था की जाए।
7. अभिभावकों की सहभागिता बढ़ाई जाए।

संदर्भ सूची

1. भारत सरकार, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय।
2. राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020।
3. शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार की वार्षिक रिपोर्ट।
4. शर्मा, आर. (2018). बालिका शिक्षा और सरकारी योजनाएँ।
5. सिंह, पी. एवं वर्मा, एस. (2019). ICDS का शैक्षिक प्रभाव।
6. गुप्ता, एम. (2020). बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का मूल्यांकन।
7. मिश्रा, डी. (2021). कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों का अध्ययन।
8. Unicef Reports On Girl Education-
9. Unesco Global Education Monitoring Reports-
10. Ncert Research Publications-

